बिन संस्कार नहीं सहकार

बिना सहकार नहीं उद्धार

छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार

वर्ष- 23 अंक - 10 | अगस्त 2026 द्वितीय पाक्षिक | RNI NO. CHHHIN/2012/45105 | प्रकाशन तिथि 02 सितम्बर | पृष्ठ-12 | मूल्य 2000/- वार्षिक

'मैं से हम' की यात्रा ही सहकारिता की शक्ति : सौरभ शर्मा

सहकारी आंदोलन को गति देने राज्य सहकारी संघ का बस्तर प्रवास

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को नई गति और व्यापक जनभागीदारी प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ का प्रतिनिधिमंडल 17 से 20 अगस्त 2026 तक बस्तर संभाग के प्रवास पर रहा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा, सहकार भारती के प्रदेश संगठन मंत्री एवं संघ के मानसेवी सदस्य श्री कनीराम शर्मा तथा सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य क्षेत्र प्रमुख श्री दिलीप पाटिल कर रहे थे।

बस्तर के सहकारी नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक

प्रवास के प्रथम दिन 17 अगस्त को बस्तर जिले के सहकारी नेतृत्व के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभागृह में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप, उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास मिश्रा, बस्तर जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री वेदांत दीक्षित, प्रदेश सहसंयोजक श्री रंजीत पांडे, सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक श्री मनोहर तिवारी, प्राधिकृत अधिकारी कोलावल श्री परेश बसेरा सहित विभिन्न विकासखंडों से आए लैम्प्स एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सहकारी नेतृत्व उपस्थित रहे।

बस्तर के गांवों में आत्मनिर्भरता का माध्यम बनेगी सहकारिता

श्री कनीराम शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में अब विकास और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं उभर रही हैं। गांव, गरीब और किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बस्तर में सहकारी संस्थाओं को मजबूत कर स्थानीय स्तर पर रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़े मॉडल को गांव-गांव पहुंचाने का आह्वान

सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य क्षेत्र प्रमुख श्री दिलीप पाटिल ने कहा कि, सहकारिता को केवल संस्था के संचालन तक सीमित न रखते हुए इसे रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय सहकारी नेतृत्व से सहकारिता की अवधारणा एवं इसके लाभों को गांव-गांव तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को सहकारी संस्थाओं से जोडने़ का आह्वान किया।

सहकारवाद वर्तमान समय की आवश्यकता

बैंक के उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि, सहकारवाद वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने सहकारी कार्यकर्ताओं से उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। वहीं बस्तर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री वेदांत दीक्षित ने सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी एवं सक्षम बनाने के संबंध में अपने विचार रखे।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सहकारी संघ के संभागीय कार्यालय का किया भ्रमण

बैठक के उपरांत राज्य सहकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर संभाग में स्थित राज्य सहकारी संघ के संभागीय कार्यालय एवं विभिन्न सहकारी समितियों का भी भ्रमण किया तथा वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल इसके बाद दक्षिण बस्तर के प्रवास के लिए रवाना हुआ। प्रवास के दौरान सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं ग्रामीणों से संवाद कर सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

सहकारिता कोई कार्यक्रम नहीं, जनआंदोलन है : शर्मा

बैठक को संबोधित करते हुए श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि,सहकारिता कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी संस्थाओं को आपसी समन्वय और सहभागिता के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सहकारिता को "मैं से हम" की यात्रा बताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही सहकारी आंदोलन को मजबूत आधार मिल सकता है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं एवं उनके नेतृत्व से सहकारिता की मूल भावना के अनुरूप मिल-जुलकर कार्य करने तथा प्रत्येक सदस्य को सहकारी आंदोलन से जोड़ने का आह्वान किया।

राज्य सहकारी संघ के वार्षिक आमसभा में बड़े फैसले : डिजिटलाइजेशन से लेकर आधुनिक प्रेस और प्रशिक्षण नीति पर जोर

■ **छग राज्य सहकारी संघ की आमसभा में AI, डिजिटलाइजेशन, आधुनिक प्रशिक्षण, अछोटी में प्रेस और 8 जिला संघों की सदस्यता समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई।**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित की वार्षिक साधारण सभा में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, तकनीक आधारित और अधिक मजबूत बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभा में सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण के विस्तार, डिजिटलाइजेशन, AI तकनीक, आधुनिक प्रबंधन, प्रकाशन व्यवस्था और संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जीई रोड रायपुर के सभागार में आयोजित वार्षिक आमसभा में संघ के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों, सदस्य संस्थाओं और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन, आय-व्यय, वित्तीय पत्रकों तथा वर्ष 2027-28 के प्रस्तावित बजट सहित विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर चर्चा की गई।

कनीराम के अनुभव और मार्गदर्शन से मजबूत होगा राज्य सहकारी संघ

सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम ने भी आमसभा को सम्बोधित किया। श्री कनीराम के सामाजिक एवं संगठनात्मक जीवन की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई, जब उन्होंने शालेय विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में प्रवेश किया। वर्ष 1984 से 1989 तक महाराष्ट्र के रामटेक में प्रचारक के रूप में कार्य करने के बाद वर्ष 1990 से 1997 तक विद्या भारती की 'सरस्वती शिशु मंदिर' विस्तार योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सक्रिय रहे। वर्ष 1993 से 2000 तक उन्होंने प्रांत के प्रथम घोष प्रमुख के रूप में दायित्व संभाला।

वर्ष 2000 से 2008 तक सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री तथा एकल विद्यालय योजना में प्रांत योजना प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2008 से 2013 तक सहकार भारती के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व निभाया। वर्ष 2013 से 2019 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-प्रांत प्रचार प्रमुख तथा 2019 से 2023 तक प्रांत प्रचार प्रमुख के रूप में उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वर्ष 2024 से वे सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री के रूप में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही वर्ष 2013 से 'शाश्वत राष्ट्रबोध' जागरण पत्रिका के प्रचार विभाग से भी जुड़े हैं।

राज्य सहकारी संघ में श्री कनीराम को मानसेवी सदस्य बनाए जाने से उनके लंबे अनुभव, संगठनात्मक दक्षता एवं मार्गदर्शन का लाभ संघ को मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी तथा प्रदेश में सहकारी आंदोलन को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

8 जिला सहकारी संघों को राज्य संघ की सदस्यता

सभा में प्रदेश के शेष 8 जिला सहकारी संघों को राज्य सहकारी संघ की सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा गया। इनमें धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कवर्धा, बलौदा बाजार, बेमेतरा, महासमुंद और गरियाबंद शामिल हैं। सदस्यता मिलने से राज्य और जिला स्तर पर सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रकाशन और जागरूकता गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में मदद मिलेगी।

अछोटी में आधुनिक प्रेस स्थापित करने की तैयारी

दुर्ग जिले के ग्राम अछोटी में संघ को प्राप्त दो एकड़ भूमि पर आधुनिक प्रेस स्थापित करने की दिशा में भी कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।

शेष पेज 03 पर ....

दलहन और मक्का में आत्मनिर्भरता के लिए नेफेड–एनसीसीएफ की बड़ी पहल

■ भारत ई–पोर्टल से लाखों किसान जुड़े, सहकारी खरीद व्यवस्था को मिल रहा विस्तार

नई दिल्ली। देश को दलहन एवं मक्का के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से खरीद एवं बाजार व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस दिशा में ह्स्नश्वष्ठ और ह्ष्ट्स्न किसानों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने तथा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना तथा दलहन के आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मक्का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, NCCF के ई-संयुक्ति पोर्टल पर 44.09 लाख से अधिक तथा NAFED के ई-समृद्धि पोर्टल पर 15.84 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। किसानों की यह व्यापक भागीदारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विकसित की जा रही डिजिटल एवं संगठित खरीद व्यवस्था की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था

पंजीकृत किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सहकारी खरीद नेटवर्क के माध्यम से उनकी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित खरीद का लाभ मिल सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार उपलब्ध होने तथा उचित मूल्य प्राप्त होने का भरोसा मजबूत होता है।

हालांकि, किसानों को केवल एमएसपी पर ही अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यदि खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत मिलती है तो किसान अपनी उपज वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार व्यवस्था में सुनिश्चित खरीद और बाजार मूल्य–दोनों का विकल्प किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

सहकारिता के माध्यम से मजबूत हो रही कृषि मूल्य श्रृंखला

NAFED का व्यापक सहकारी नेटवर्क किसानों को संगठित करने तथा कृषि उपज की खरीद एवं विपणन के लिए संस्थागत आधार प्रदान करता है। वहीं ह्ष्ट्स्न डिजिटल पंजीकरण, किसान संपर्क एवं बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है। दोनों संस्थाओं की संयुक्त पहल से उत्पादन, खरीद और बाजार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

दलहन उत्पादन में वृद्धि देश की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की आय के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित खरीद से किसानों को इन फसलों की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, मक्का को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादन के साथ-साथ इथेनॉल क्षेत्र की आवश्यकता भी पूरी करने में मदद मिलेगी।

सहकार से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

NAFED और NCCF की यह पहल 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल पंजीकरण, सहकारी खरीद, एमएसपी का आश्वासन और खुले बाजार में बिक्री की स्वतंत्रता को एक साथ जोड़कर किसानों को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

यह मॉडल छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां सहकारी समितियों, पैक्स और किसान उत्पादक समूहों के माध्यम से दलहन एवं मक्का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने तथा राज्य को कृषि क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं।

अमूल बना विश्व का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड

■ भारत के किसान–स्वामित्व वाले सहकारी मॉडल को वैश्विक पहचान

नई दिल्ली। भारत के सहकारी डेयरी आंदोलन के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। Brand Finance Food & Drink 2026 के नवीनतम अध्ययन में अमूल को विश्व का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड घोषित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल अमूल की ब्रांड शक्ति को दर्शाती है, बल्कि भारत के किसान-स्वामित्व वाले सहकारी मॉडल की वैश्विक सफलता को भी रेखांकित करती है।

अध्ययन के अनुसार अमूल की ब्रांड वैल्यू में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। अमूल को 93.0 का Brand Strength Index (BSI) प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर उसे AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग मिली है। वैश्विक स्तर पर अमूल सबसे मजबूत खाद्य ब्रांडों में दूसरे स्थान पर तथा सबसे मूल्यवान डेयरी ब्रांडों में चौथे स्थान पर रहा है।

सहकारिता के लिए प्रेरणादायक मॉडल है अमूल

अमूल को मिली यह वैश्विक मान्यता केवल एक ब्रांड की सफलता नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि किसानों की सामूहिक शक्ति, सहकारिता, पारदर्शी प्रबंधन, गुणवत्ता, नवाचार और बाजार से सीधा जुड़ाव किसी भी सहकारी संस्था को वैश्विक स्तर का उद्यम बना सकता है।

छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में डेयरी एवं बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विकास के लिए अमूल मॉडल एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बन सकता है। किसान स्वामित्व, स्थानीय स्तर पर संगठन और मजबूत विपणन व्यवस्था के माध्यम से सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

अमूल की इस सफलता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका किसान-केंद्रित सहकारी ढांचा है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) से जुड़े 18 सदस्य दुग्ध संघों के माध्यम से लगभग 18,600 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां और 36.4 लाख उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क प्रतिदिन औसतन लगभग 3.2 करोड़ लीटर दूध की खरीद करता है। इस प्रकार अमूल की ब्रांड सफलता के पीछे देश के लाखों दुग्ध उत्पादकों की सामूहिक भागीदारी है।

अमूल की आर्थिक मजबूती भी लगातार बढ़ रही है। GCMMF ने वर्ष 2024-25 में 65,911 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 59,545 करोड़ रुपये था। दूध एवं दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, पारंपरिक मिठाइयों सहित अनेक खाद्य श्रेणियों में अमूल ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

अमूल ने भारतीय सहकारी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत स्थान दिलाया है। इसके उत्पाद 50 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के साथ अमूल भारतीय किसानों द्वारा संचालित सहकारी उद्यम की क्षमता को वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है।

बीजापुर में जिला सहकारी संघ के गठन की पहल तेज, आवश्यक बैठक आयोजित

बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ की स्थापना के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई है। राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल (बोर्ड) द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जिला सहकारी संघों के गठन के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बीजापुर जिले में नवीन जिला सहकारी संघ के गठन की दिशा में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने जिले की सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजापुर जिले में जिला सहकारी संघ के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना तथा जिले की सहकारी संस्थाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना रहा।

इस अवसर पर प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ स्थापित करने का निर्णय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी संघों की स्थापना से जिले में कार्यरत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जिला सहकारी संघ सहकारी संस्थाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को राज्य स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। साथ ही प्रशिक्षण, सहकारी शिक्षा, सदस्यता विस्तार, जनजागरूकता, क्षमता विकास एवं सहकारी गतिविधियों के प्रभावी संचालन को भी नई गति मिलेगी।

इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर संघ के मानसेवी सदस्य एवं सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम शर्मा, सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य क्षेत्र प्रमुख श्री दिलीप पाटिल सहित केजी सुधारक, संदीप तेलम, जितेन्द्र तेलम, संतोष, सोनू राव, पुरूषोत्तम, पुष्पा सिन्हा, भारती निषाद, अवध राम सिन्हा, मुन्गलाल जुमड़े, श्रीनिवास राव एवं पुरूषोत्तम भंडारी आदि उपस्थित थे।

प्रमाणपत्र के बाद पहली बैठक कंधों पर बंटी ज़िम्मेदारी

संकलनकर्ता : श्री पुरूषोत्तम सोनी, प्रभारी व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर

विशेष श्रृंखला भाग-2 : प्रबंध समिति — सामूहिक नेतृत्व की नींव

पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि कैसे एक गाँव के बिखरे स्वरों ने 'हम' की भाषा अपनाकर सहकारी समिति की नींव रखी। पंजीयन प्रमाणपत्र मिलने के कुछ ही दिनों बाद, उसी गाँव में एक और बैठक बुलाई गई – इस बार सवाल थाः संस्था चलाएगा कौन? यहीं से शुरू होती है प्रबंध समिति की कहानी, जो अकेले 'मैं' के फैसलों को सामूहिक 'हम' के नेतृत्व में बदलने का पहला व्यावहारिक कदम है।

सामूहिक नेतृत्व की नींव

जब पंजीयन की खुशी थोड़ी शांत हुई, तो गाँव के बुजुर्ग शिक्षक ने फिर एक बार सबको इकट्ठा किया। इस बार सवाल पूछा – 'अब संस्था का हिसाब-किताब, फैसले, रोज़मर्रा का काम कौन देखेगा?' कुछ देर की चुप्पी के बाद एक युवा सदस्य ने कहा, 'हम सब मिलकर।' यही जवाब सही निकला। कोई भी सहकारी समिति किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती – उसका संचालन एक निर्वाचित प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अलग-अलग सदस्य अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं।

प्रबंध समिति दरअसल पूरी सदस्यता की ओर से भरोसे का प्रतिनिधित्व करती है। जो सदस्य समिति में चुने जाते हैं, वे किसी विशेषाधिकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा और उत्तरदायित्व की भावना से चुने जाते हैं – यह भावना जितनी मज़बूत होगी, संस्था उतनी ही स्थिर रहेगी।

पारदर्शी चुनाव — विश्वास की पहली परीक्षा

प्रबंध समिति के गठन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। एक अनुभवी सहकारिता अधिकारी अक्सर नई समितियों को यही सलाह देते हैं कि चुनाव प्रक्रिया चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसमें पारदर्शिता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

"चुनाव का तरीका छोटा हो सकता है, पर उसकी निष्पक्षता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए – यहीं से सदस्यों का भरोसा बनना शुरू होता है।"

— वरिष्ठ सहकारिता अधिकारी

जिन समितियों में शुरुआत से ही चुनाव खुले मन से, बिना दबाव और बिना पक्षपात के कराए गए, वहाँ आगे चलकर सदस्यों की सक्रिय भागीदारी भी अधिक देखी गई। इसके उलट, जहाँ चुनाव नाम मात्र की औपचारिकता बनकर रह गए, वहाँ धीरे-धीरे सदस्यों की रुचि कम होती चली गई।

सामूहिक निर्णय बनाम व्यक्तिगत निर्णय

दो पड़ोसी समितियों की कहानी इस फ़र्क़ को अच्छी तरह समझाती है। एक समिति में हर फैसला – चाहे छोटा हो या बड़ा – प्रबंध समिति की बैठक में सामूहिक चर्चा के बाद ही लिया जाता था। दूसरी समिति में अध्यक्ष अक्सर अकेले ही निर्णय ले लेते थे, बाद में समिति को केवल सूचित कर दिया जाता था।

कुछ ही महीनों में फ़र्क़ साफ दिखने लगा – पहली समिति में सदस्यों का उत्साह बढ़ता गया, जबकि दूसरी समिति में असंतोष पनपने लगा। आखिरकार दूसरी समिति के सदस्यों ने खुद आगे आकर याद दिलाया कि निर्णय सामूहिक होने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं।

"एक व्यक्ति का फैसला जल्दी हो सकता है, पर सामूहिक फैसला टिकाऊ होता है – यही सहकारिता की असली ताकत है।"

जवाबदेही की संस्कृति

प्रबंध समिति का गठन केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं है। हर पद के साथ जवाबदेही जुड़ी होती है – कोषाध्यक्ष को हिसाब-किताब की स्पष्टता रखनी होती है, सचिव को अभिलेख व्यवस्थित रखने होते हैं, और अध्यक्ष को सबको साथ लेकर चलना होता है। जिन समितियों में यह जवाबदेही स्पष्ट रूप से बाँटी गई, वहाँ काम सुचारू रूप से चला।

एक सफल समिति के सचिव बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि ज़िम्मेदारी बाँटने से नियंत्रण कमज़ोर होगा। पर अनुभव ने यह सिखाया कि ज़िम्मेदारी बाँटने से भरोसा बढ़ता है, बोझ नहीं।

नई समितियों के लिए सीख

जो समितियाँ शुरुआत से ही स्पष्ट भूमिका-विभाजन, नियमित बैठकें और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाती हैं, वे आगे चलकर बड़ी चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर पाती हैं। प्रबंध समिति का गठन इसलिए केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि समिति की दीर्घकालिक सफलता की नींव है।

अगले अंक में हम पढ़ेंगे – पहली आमसभा की कहानी, जहाँ सदस्य पहली बार सामूहिक रूप से अपनी संस्था का हिसाब-किताब समझने और सवाल पूछने के लिए इकट्ठा होते हैं। तब तक के लिए, सहकार समाचार पढ़ते रहिए।

पेज 01 का शेष ....

राज्य सहकारी संघ के वार्षिक आमसभा में बड़े फैसले :

वर्तमान में सहकारी समाचार, प्रशिक्षण सामग्री और अन्य प्रकाशनों के मुद्रण के लिए बाहरी संस्थाओं पर निर्भरता है। आधुनिक प्रेस स्थापित होने से प्रकाशन कार्य में आत्मनिर्भरता के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ने की उम्मीद है।

AI और डिजिटल तकनीक पर विशेष जोर

सहकारी संघ के कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए AI, डिजिटल मीडिया, ई-लर्निंग, डेटा प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास और ई-गवर्नेंस जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (Mou) करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

नई सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण नीति

नई सहकारी शिक्षा-प्रशिक्षण नीति तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, संचालकों और सदस्यों को प्रबंधन, लेखांकन, वित्तीय अनुशासन और आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूरा करने वाले कर्मचारियों को बोनस अंक का प्रस्ताव

सभा में राज्य सहकारी संघ से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, चयन अथवा अन्य सेवा लाभों में निर्धारित बोनस अंक देने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक प्रावधान करने पर भी चर्चा हुई।

आमसभा ने रू. 15 करोड़ के बजट को दी मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रू. 5 करोड़ के अनुपूरक बजट तथा वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए रू. 10 करोड़ के मुख्य बजट का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे संघ की आगामी गतिविधियों, योजनाओं एवं सहकारी विकास कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा कार्यालयीन कार्य, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार को आधुनिक बनाने के लिए कम्प्यूटर, कैमरा, माइक्रोफोन, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर और नेटवर्किंग संसाधनों की खरीदी का प्रस्ताव रखा गया।

सदस्यता अभिदाय बढ़ाने पर भी विचार

संघ की बढ़ती गतिविधियों और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए सदस्य संस्थाओं से मिलने वाले वार्षिक सदस्यता अभिदाय को 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ से मार्गदर्शन लेने की बात कही गई।

ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

सभा में राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, विपणन संघ के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी, हाथकरघा संघ के प्राधिकृत अधिकारी भोजराम देवांगन, संघ के मानसेवी सदस्य एवं सहकार भर्ती प्रदेश महामंत्री कनीराम शर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के उपाध्यक्ष नरेश यदु, रायपुर बैंक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा, उपाध्यक्ष अमितेश कश्यप, जिला सहकारी संघों के प्रतिनिधिगण, पंजीयक प्रतिनिधि विश्वदीप महोबे, उपायुक्त रायपुर के सहायक आयुक्त विनय कश्यप, संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.सी. ध्रुव सहित संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मार्कफेड की उच्चस्तरीय बैठक

धान खरीदी, खाद वितरण, वित्तीय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास की हुई समीक्षा

■ प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी बोले- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने पर है जोर

रायपुर। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों को समय से पहले अंतिम रूप देने और किसानों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) में प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीदी, खाद वितरण, वित्तीय प्रबंधन तथा शाखावार कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

2025-26 सीजन में खरीदे गए धान की स्थिति की समीक्षा

बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उपार्जित धान के निराकरण, मिलर्स द्वारा धान उठाव, भारतीय खाद्य निगम एवं नान में चावल जमा, कस्टम मिलिंग, परिवहन व्यवस्था तथा समितियों में उपलब्ध शेष धान की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को धान के समयबद्ध निराकरण एवं भंडारण क्षमता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आगामी खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपार्जन केंद्रों की अधोसंरचना, बारदाना उपलब्धता, आवश्यक उपकरण, मानव संसाधन, किसान पंजीयन, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं विद्युत व्यवस्था को समय पर पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उर्वरक वितरण व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा

बैठक में उर्वरक वितरण व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की गई। यूरिया, डीएपी, एनपीके सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता, समितिवार वितरण, भंडारण, स्टॉक सत्यापन, परिवहन व्यवस्था तथा आगामी सीजन की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लेखा शाखा की समीक्षा के दौरान आय-व्यय, वित्तीय स्थिति, लंबित देयकों की वसूली, भुगतान, ऑडिट आपत्तियों के निराकरण, बैंक मिलान तथा लंबित अग्रिम राशि के समायोजन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समितियों के लंबित प्रकरणों, शिकायतों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा कर शाखावार जिम्मेदारियां और समय-सीमा निर्धारित की गई। प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने सभी शाखा एवं कक्ष प्रभारियों को निर्देशित किया कि लंबित कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें, व्यवसायिक गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा आगामी समीक्षा बैठक में अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करें।

जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के परिणाम घोषित

भाठागांव विद्यालय की कुमारी नैना कोसले जिला स्तर पर रही प्रथम

धमतरी। जिला सहकारी संघ धमतरी द्वारा भारत शासन सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 6 जुलाई 2026 को जिले के चार विकासखंड के पांच परीक्षा केंद्र विद्यालय में "सहकार से समृद्धि" विषय पर 13 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 232 छात्र-छात्राओं ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में शामिल हुए।

गत दिवस संघ द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता परिणाम की घोषणा की गई। जिसमें जिला स्तर पर भाठागांव विद्यालय के कुमारी नैना कोसले प्रथम, मगरलोड विद्यालय के कुमारी क्षमता साहू द्वितीय तथा मेनोनाइट उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी की कुमारी वेणिका सेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संघ द्वारा क्रमशः इन्हें 3100, 2100 तथा 1100 की धनराशि चेक द्वारा दिया गया।

धमतरी विकासखंड से ये रहे विजेता

धमतरी विकासखंड से शिव सिंह वर्मा विद्यालय धमतरी से कुमारी हर्ष लता प्रथम, कुमारी प्रिया ढीमर द्वितीय तथा तृतीय स्थान विद्यालय भोथली की कुमारी विद्या ने व विकासखंड कुरुद स्तर पर विद्यालय भाठागांव की कुमारी पद्मिनी साहू प्रथम, कुमारी झरना साहू द्वितीय तथा कुमारी पुष्पांजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विकासखंड मगरलोड स्तर पर मगरलोड की कुमारी रिया कुर्रे प्रथम, कुंडेल विद्यालय की कुमारी झरना निषाद द्वितीय व मेघा विद्यालय की कुमारी गुंजा पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

नगरी विकासखंड में ये रहे विजेता

नगरी विकासखंड स्तर पर पीएमश्री श्रृंगी ऋषि शासकीय विद्यालय नगरी के कुमारी आराधना निषाद प्रथम, ज्योति मंडावी द्वितीय तथा गायत्री सोरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संघ द्वारा विकासखंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को 1001, 701 व 501 की धनराशि सहित समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरण हेतु पांच परीक्षा केंद्र विद्यालय में भेजा गया है। जिसमें सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र का वितरण 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस पर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

इनकी रही भागीदारी

निबंध लेखन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में प्रदीप ठाकुर उपायुक्त सहकारिता धमतरी, मधुलिका तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के निर्देश एवं धमतरी, कुरूद, नगरी व मगरलोड विकासखंड के सहकारिता विस्तार अधिकारी संगीता सिन्हा, जितेंद्र नंदा, नेमीचंद देव व भुनेश्वर नेताम, जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू, प्रबंधक ए पी गुप्ता सहित समस्त परीक्षा केंद्र प्राचार्य की सक्रिय भागीदारी रही। उक्ताशय की जानकारी जिला सहकारी संघ धमतरी द्वारा दी गई।

पैक्स में कारोबार के आधार पर स्टाफिंग मानदंड प्रस्तावित

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के कम्प्यूटरीकरण एवं डिजिटल रूपांतरण के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), एलएएमपीएस एवं किसान सेवा समितियों के लिए मसौदा मॉडल मानव संसाधन नीति प्रस्तावित की गई है। नीति का उद्देश्य समितियों में आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन, पारदर्शी भर्ती, उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, कैरियर प्रगति एवं प्रदर्शन आधारित कार्यप्रणाली विकसित करना है।

मसौदा नीति में पीएसीएस का वर्गीकरण पिछले तीन वर्षों के औसत ऋण एवं गैर-ऋण कारोबार के आधार पर ए+ से एफ तक सात श्रेणियों में करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार 10 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली ए+ श्रेणी की पीएसीएस में न्यूनतम 7 कर्मचारी रखने का प्रावधान प्रस्तावित है। इनमें सचिव, प्रबंधक, लेखाकार/सहायक कार्यकारी, दो विशेषज्ञ तथा दो क्लर्क/डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे।

इसी प्रकार 5 से 10 करोड़ रुपये के कारोबार वाली समितियों में 6, 3 से 5 करोड़ में 5, 1 से 3 करोड़ में 4 तथा 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के कारोबार वाली पीएसीएस में न्यूनतम 3 कर्मचारियों का प्रावधान प्रस्तावित है। 25 से 50 लाख तथा 25 लाख रुपये तक के कारोबार वाली समितियों में कम से कम 2 कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रस्ताव है। छोटी समितियों में साझा सचिव की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन मेकर-चेकर सिद्धांत के अनुरूप कुल कर्मचारी संख्या दो से कम नहीं होगी।

मसौदे में स्टाफ की संख्या को पीएसीएस के व्यवसाय विस्तार से जोड़ने का भी प्रावधान है। निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति होने पर अतिरिक्त क्लर्क/डीईओ, विशेषज्ञ तथा प्रबंधकीय या लेखा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त वेतन एवं प्रशासनिक व्यय आगामी तीन वर्षों में पीएसीएस की आय से वहन किया जा सके।

भर्ती प्रक्रिया को योग्यता एवं पारदर्शिता आधारित बनाने के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का प्रावधान प्रस्तावित है। सहकारी क्षेत्र की मान्यता प्राप्त योग्यताओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। भर्ती स्वतंत्र एजेंसी अथवा राज्य स्तरीय भर्ती निकाय के माध्यम से कराए जाने का विकल्प भी रखा गया है।

नीति में कर्मचारियों के लिए संरचित वेतनमान, निश्चित समेकित पारिश्रमिक तथा प्रदर्शन आधारित परिवर्तनीय वेतन जैसे विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रोत्साहन, कैरियर प्रगति, कर्मचारी कल्याण एवं सेवानिवृत्ति लाभ को भी मानव संसाधन नीति का हिस्सा बनाया गया है।

जिला स्तरीय पीएसीएस समिति (DLPC) द्वारा स्टाफिंग, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, सेवा अभिलेख, अनुशासनात्मक मामलों, लेखापरीक्षा अनुपालन एवं व्यवसाय विकास की निगरानी की जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय पीएसीएस समिति (SLPC) द्वारा राज्य स्तर पर निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

यह मॉडल नीति पीएसीएस में तदर्थ नियुक्तियों को कम करने, कौशल अंतर को दूर करने तथा डिजिटल एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम मानव संसाधन विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति लागू करने में आवश्यक लचीलापन भी प्रदान किया गया है।

सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने पर प्रशिक्षण

- **महिलाओं को सहकारिता से स्वरोजगार एवं समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की दी गई जानकारी**

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में तथा प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरव शर्मा के मार्गदर्शन में आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केन्द्र बड़े मारेंगा में "सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर कैसे बनें" विषय पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 अगस्त 2026 को आयोजित प्रशिक्षण में सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा ने महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व एवं लाभ, नई सहकारी समिति के पंजीयन की प्रक्रिया तथा सहकारी संस्था के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार एवं आय के अवसर विकसित करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना, स्वरोजगार के अवसर तथा सहकारिता के माध्यम से समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, इस पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

संगठित हों महिलाएं

श्री झा ने कहा कि, सहकारिता के माध्यम से महिलाएं संगठित होकर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित कर सकती हैं। सामूहिक प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को भी गति मिलेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सुदन मौर्य का विशेष प्रयास एवं सहयोग रहा। प्रशिक्षण में उपस्थित महिलाओं ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढने में रुचि व्यक्त की।

सहकारी बैंक दुर्ग के संचालक मण्डल एवं ऋण उप समिति की बैठक

दुर्ग। श्री प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की अध्यक्षता में 14 अगस्त को संचालक मण्डल एवं ऋण उप समिति की बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में श्री नरेष यदु उपाध्यक्ष, श्री सुमन कुमार कोर्राम सहायक संचालक कृषि, श्री सतीष पाटले उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग एवं श्री एस.के.वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

गन्ना-टमाटर-गोभी के लिए दिया गया ऋण

बैंक के कार्यक्षेत्र जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा के अंतर्गत 22 सहकारी समितियों से संबंधित कृषकों का फसल ऋणों हेतु पूरक साख सीमा 2026-27 से 2028-29 हेतु 1833 किसानों को 20.55 करोड़ रु., गन्ना उत्पादन हेतु 7 कृषक को साख सीमा 17.45 लाख रु., कपास उत्पादन हेतु 1 कृषक को 1 लाख, उद्यानिकी फसल हाइब्रीड टमाटर हेतु 4 किसानों को 3.64 लाख रु., उद्यानिकी फसल गोभी हेतु 1 किसान को 1.38 का ऋण स्वीकृत किया गया है।

गैर कृषि ऋण भी दिए गए

गौपालन हेतु 78 किसानों को 1.28 करोड़ एवं नवीनीकरण अंतर्गत 33 किसानों को 56.19 लाख, मत्स्य पालन अंतर्गत 3 किसानों को 7.44 लाख, बकरीपालन हेतु 2 कृषको को 2.38 लाख, कुक्कुट पालन हेतु 2 किसानों को 6 लाख, मध्यकालीन व्यक्तिगत ऋण अंतर्गत 1 किसान को 2 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार अन्य हितग्राहियों के मांग अनुसार अकृषि ऋण स्वीकृत किया गया।

योजनाओं के प्रचार-प्रसार का निर्णय

बैंक के माध्यम से ऋणनीति अनुसार उप संचालक कृषि/ उद्यानिकी/ पशुपालन/ मत्स्य विभाग के विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कृषकों के मध्य करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ताकि बैंक के माध्यम से इन योजनाओं में अधिकाधिक कृषक लाभान्वित हो। बैठक में सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक, श्री एस.पी. वाहने शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह पर बस्तर की महिलाएं

तेलीमारेंगा में महिलाओं को दिया सहकारी एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में तथा संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केंद्र तेलीमारेंगा में महिलाओं के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 19 अगस्त को आयोजित प्रशिक्षण में महिलाओं को "सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर कैसे बना जाए" विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा ने महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य समझाते हुए बताया कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से महिलाएं अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर सकती हैं। प्रशिक्षण में लघु, छोटे एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, सामूहिक रूप से व्यवसाय संचालित करने तथा नई सहकारी समिति के पंजीयन की प्रक्रिया एवं आवश्यक विधियों की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारी श्रीमती वैदेही मौर्य ने महिलाओं को आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता को आवश्यक बताया।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार एवं सामूहिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं, जिनका प्रशिक्षकों द्वारा समाधान किया गया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में संभागीय कार्यालय श्री सुदन मौर्य का विशेष योगदान रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को सहकारिता से जोड़कर आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

पीएम-कुसुम योजना में पैक्स की बढ़ रही भूमिका

सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से किसानों को ऊर्जा सुरक्षा व अतिरिक्त आय का अवसर

नई दिल्ली। देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा पीएसीएस स्तर पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अभिसरण को प्रमुख पहल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, डीजल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा ऊर्जा एवं जल सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके तहत पीएसीएस से जुड़े किसान सौर कृषि पंप अपना सकते हैं तथा खेतों एवं उपयुक्त भूमि पर सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

सौर ऊर्जा उत्पादन में पीएसीएस को अवसर

पीएम-कुसुम के घटक-ए के तहत किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, एफपीओ और जल उपयोगकर्ता संघ विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। निर्धारित शर्तों के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित कर उत्पादित बिजली को संबंधित डिस्कॉम को बेचने की व्यवस्था है।

इस व्यवस्था में पीएसीएस अपनी पारंपरिक ऋण एवं कृषि सेवा भूमिका से आगे बढ़कर स्थानीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकती हैं। बंजर एवं गैर-कृषि योग्य भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने के साथ कुछ परिस्थितियों में कृषि भूमि पर स्टिल्ट-माउंटेड सौर परियोजनाओं की भी संभावना है, जिससे कृषि गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं।

किसानों को सस्ती और विश्वसनीय सिंचाई

पीएसीएस के माध्यम से किसानों को सौर सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने का भी अवसर है। स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने से किसानों के सिंचाई खर्च में कमी आने और दिन के समय अधिक विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध होने की संभावना है।

सौर ऊर्जा के उपयोग से डीजल एवं बिजली पर होने वाले नियमित खर्च में कमी के साथ किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं। वहीं, सौर परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले किसानों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भूमि पट्टे से आय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

पीएसीएस के लिए आय का नया स्त्रोत

पीएम-कुसुम का पीएसीएस से जुड़ाव सहकारी संस्थाओं के लिए आय एवं व्यावसायिक गतिविधियों का नया क्षेत्र खोल सकता है। यदि कोई पीएसीएस विकेंद्रीकृत सौर परियोजना में निवेश अथवा भागीदारी करती है, तो वह अपने सदस्यों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा से आय अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां पीएसीएस पहले से ही किसानों के साथ सीधे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। ऐसे में पीएसीएस कृषि ऋण, उर्वरक, बीज और अन्य सेवाओं के साथ ऊर्जा एवं सिंचाई समाधान उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित हो सकती हैं।

पीएम-कुसुम से लाखों किसानों को लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक पीएम-कुसुम योजना से 21.77 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके थे। वहीं 31 जुलाई 2026 तक योजना के घटक-ए के तहत 8,067.50 मेगावाट क्षमता स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 1,602.45 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी थी। घटक-बी के तहत 8,07,256 स्टैंडअलोन सौर पंप स्थापित किए जा चुके थे।

सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एन कुमार साहू सम्मानित

■ साईं बुनकर समिति रेवाडीह में रास्ट्रीय हथकरघा दिवस संपन्न

राजनांदगांव। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर साई बुनकर सहकारी समिति मर्यादित रेवाडीह के बुनकर कर्मशाला में सहकारी संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बुनकरों के उकृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने समिति के बुनकरों द्वारा बुनाई किए जा रहे संबलपुरी साड़ी को उनकी कौशल का नई पहचान बताया। इस अवसर पर बुनकरों के साथ-साथ हथकरघा और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोंगों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में सहकारिता आंदोलन से जुड़े श्री एन कुमार साहू प्रभारी प्रबंधक जिला सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव को भी सम्मानित किया गया।

इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर उपस्थित थे - मुख्य अतिथि - श्री राकेश ठाकुर से.नि. प्रबंधक हथकरघा, श्री शैलेन्द्र तिवारी से.नि. उप संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग, श्री एल. डी. निमजे से.नि. सहायक संचालक हथकरघा, श्री अमलेंदु हाजरा पूर्व लोकपाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बी. पी. वासनिक से.नि. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्री संतोष साहू ग्रामोद्योग राजनांदगांव सहित श्री साईं बुनकर सहकारी समिति रेवाडीह के अध्यक्ष श्री चूड़ामणि देवांगन एवं समिति के समस्त पदाधिकारी तथा वृहत संख्या में बुनकर सदस्यगण उपस्थित थे।

इस साल ज्यादा किसानों ने उठाया कृषि ऋण का लाभ

■ **प्रधानमंत्री फसल बीमा आवरण सुरक्षा में भी दिखाई अधिक रुचि**

दुर्ग। 19 अगस्त की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अधीनस्त कार्यरत 402 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2026 के लिए निर्धारित कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 1595 करोड़ के विरुद्ध 1412 करोड़ रुपयों का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण कर तीनो जिले में कुल 3,08,674 कृषकों को लाभान्वित किया है। यह गत 4 वर्षों में रिकार्ड ऋण वितरण है।

लक्ष्य का 89% पूर्ति सुनिश्चित

उल्लेखनीय है कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.दुर्ग द्वारा खरीफ2026 में छ.ग.शासन द्वारा निर्धारित पूर्व ऋण अनुपात 60 अनुपात 40 में वृद्धि कर 70 अनुपात 30 के अनुसार नकद एवं वस्तु ऋण वितरण किया गया है, कुछ समय खाद की आपूर्ति प्रभावित रहने पर भी बैंक एवं समितियों द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है। कुल निर्धारित लक्ष्य का 89% पूर्ति सुनिश्चित कर ली गयी है।

30 सितंबर तक बांटे जाएंगे ऋण

उल्लेखनीय है कि खरीफ सत्र में ऋण वितरण 30.09.2026 तक किया जाएगा तथा शासन की योजना अनुसार कृषकों को कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया जा रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर कुल कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही वितरित किया जा रहा है जो कि 4.02 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर ऋण वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवरण

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा भारत सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका अंतिम तिथि 14.08.2026 निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि तक जिलों के 3,27,027 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवरण प्रदान कर प्रीमियम बीमा कंपनी को प्रेषित की जा रही है, उल्लेखनीय है कि गत वर्ष खरीफ2025 में समितियों द्वारा 3,24,469 कृषकों को ही बीमा आवरण हुआ था जिसमें इस वर्ष 3000 नवीन कृषकों की वृद्धि हुई है एवं उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवरण प्रदान किया गया जो रिकॉर्ड स्तर पर है। बैंक द्वारा प्रीमियम राशि भुगतान प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में सभी समिति में मांग अनुसार खाद उपलब्ध है तथा कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

तकनीक आधारित सहकारी विकास को केंद्र का बढ़ावा

पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और डिजिटल निगरानी पर जोर

नई दिल्ली। देश में सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही प्रमुख सहकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी की अध्यक्षता में 27 एवं 31 अगस्त को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में दो दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सहकारी क्षेत्र की जमीनी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण, नई सहकारी समितियों के गठन एवं निष्क्रिय समितियों के पुनरुद्धार, सदस्यता विस्तार, डाटा सत्यापन तथा मॉडल उपविधियों को अपनाने सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

डिजिटल निगरानी से मजबूत होगी सहकारी व्यवस्था

बैठक में सक्रिय एवं निष्क्रिय सहकारी समितियों के आंकड़ों की समीक्षा के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र से संबंधित डाटा की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया। NCD Portal 3.0 तथा NCD GeoTag Mobile Application के माध्यम से सहकारी संस्थाओं की डिजिटल निगरानी, सत्यापन एवं प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

पैक्स के माध्यम से विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण परियोजनाओं की प्रगति भी समीक्षा का महत्वपूर्ण विषय रही। इन परियोजनाओं के जरिए गांवों के स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करने, किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराने तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य है।

सहकारी बैंकों का होगा आधुनिकीकरण

सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण को भी बैठक में विशेष महत्व दिया गया। बैंकिंग संस्थाओं में नई तकनीक के बेहतर एकीकरण तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई, ताकि सहकारी बैंक अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

इसके अलावा डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों से संबंधित आंकड़ों के सत्यापन तथा सदस्यता विस्तार की भी समीक्षा की गई। अधिक से अधिक लोगों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने और सहकारी आंदोलन का व्यापक विस्तार करने पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर जोर

बैठक में सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण को भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई। सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

यह पहल इस दृष्टिकोण को रेखांकित करती है कि सहकारी संस्थाओं का तकनीकी रूपांतरण केवल कम्प्यूटर एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित न होकर प्रशिक्षित मानव संसाधन और बेहतर संस्थागत क्षमता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

'सहकार से समृद्धि' को तकनीक का आधार

समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य के अनुरूप एक मजबूत, समावेशी एवं तकनीक-सक्षम सहकारी तंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण एवं जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों और सदस्यों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

बैठक में अपर सचिव पंकज कुमार बंसल एवं सिद्धार्थ जैन, संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा, रमन कुमार एवं शिवपाल सिंह सहित सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'आदिवासी सदस्य शिक्षा योजना' : किसानों को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

■ **मारेंगा की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारिता के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली की दी गई जानकारी**

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में 'आदिवासी सदस्य शिक्षा योजना' अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, मारेंगा के सदस्यों के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा द्वारा प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों एवं समिति सदस्यों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत एवं लाभ, समिति के उद्देश्य तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही संचालक मंडल की बैठकों के महत्व, आमसभा की भूमिका तथा समिति में संधारित किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख एवं रिकॉर्ड के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

दी गईं महत्वपूर्ण जानकारियां

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस 22 अगस्त को समिति के प्रबंधक श्री बलराम सेठिया ने सदस्यों को सहकारी ऋण नीति, संस्था के लेखा-जोखा तथा खाद वितरण व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने समिति के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों एवं समिति सदस्यों को सहकारी संस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए उन्हें अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करना तथा सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सुदन मौर्य का विशेष योगदान रहा।

‘आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना’ : सिवनी में लेंपस के कृषक सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

■ **बताया गया- ग्रामीण आर्थिक विकास का माध्यम है सहकारिता**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा इफ्को जगदलपुर एवं बस्तर जिला सहकारी संघ के सहयोग से ‘आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना’ अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोनारपाल के आश्रित ग्राम पंचायत सिवनी में लेंपस के कृषक सदस्यों का सहकारी प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान संभागीय कार्यालय जगदलपुर के वरिष्ठ प्रशिक्षक विवेक पांडे द्वारा ग्राम विकास की बुनियादी आवश्यकता प्राथमिक पाठशाला ग्राम पंचायत व सहकारी समिति को बताते हुए प्रत्येक ग्रामों में सहकारिता के विस्तार हेतु भारत सरकार के पहल पर वर्ष 2029 तक सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के स्थापना पर जानकारी देते हुए सहकारिता को ग्रामीण आर्थिक विकास का माध्यम बताते हुए सहकारी समितियों के गठन पंजीयन पर विस्तार से जानकारी दी गई।

नैनो उर्वरकों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के दौरान इफ्को के वैभव पांडे के द्वारा इफ्को के उत्पाद विशेष कर नैनो यूरिया नैनो डी.ए.पी. के साथ-साथ नैनो जिंक व नैनो कॉपर पर भी ज्ञान करते हुए संकट हरण बीमा योजना की जानकारी कृषकों को प्रदान की गई।

किसानों के विकास से ही होगा गांवों का विकास

बस्तर जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री द्विवेदी ने कहा कि, 2047 तक भारत को विकसित करने हेतु गांव को विकसित करना होगा। गांव तभी विकसित होगा जब कृषक विकसित होंगे कृषक को विकसित करने के लिए खेती को मजबूत करना होगा खेती जैविक आधार पर हो इस हेतु दुग्ध सहकारिता, मत्स्य सहकारिता के गठन पर विचार व्यक्त किया गया, वहीं लेंपस सोनारपाल के प्रबंधक श्री प्रेमनाथ वेद द्वारा लेंपस द्वारा के.सी.सी. के माध्यम से प्रदान किया जा रहे ऋण वितरण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में लेंपस सोनारपाल ग्राम पंचायत सिवनी के पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर कोटवार का सहयोग सराहनीय रहा ।

नाबार्ड ने बढ़ाया सहकारी ऋण तंत्र को वित्तीय सहयोग

डीसीसीबी को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त 33,785.65 करोड़ रुपये पहुंचा, सहकारी विकास कोष के खर्च में 93% वृद्धि

मुंबई। देश के सहकारी ग्रामीण ऋण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में नाबार्ड (NABARD) ने वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को नाबार्ड का प्रत्यक्ष पुनर्वित्त बढ़कर 33,785.65 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष 2024-25 में 27,767.64 करोड़ रुपये था। इस प्रकार एक वर्ष में इसमें 6,018.01 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

नाबार्ड के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, उसके पुनर्वित्त पोर्टफोलियो में उत्पादन एवं विपणन ऋण के रूप में 1,81,068.83 करोड़ रुपये तथा मध्यम एवं दीर्घकालिक परियोजना ऋण के रूप में 2,89,283.02 करोड़ रुपये शामिल रहे। पुनर्वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं।

पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण को मिला वित्तीय बल

सहकारी ऋण व्यवस्था के जमीनी स्तर को आधुनिक बनाने के लिए चल रही पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना में भी नाबार्ड की वित्तीय भूमिका महत्वपूर्ण रही। वर्ष 2025-26 में परियोजना के अंतर्गत 83.22 करोड़ रुपये का व्यय/समायोजन दर्ज किया गया। कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य पीएसीएस को आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार करना है।

सहकारी विकास कोष में 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नाबार्ड के सहकारी विकास कोष (CDF) के माध्यम से किए गए व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में 54.55 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 105.25 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार सहकारी विकास कोष के खर्च में लगभग 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2026 के अंत में इस कोष का शेष 300 करोड़ रुपये था।

विभिन्न विकास निधियों के अंतर्गत नाबार्ड का कुल प्रचारात्मक व्यय 280.32 करोड़ रुपये रहा। इसमें उत्पादक संगठन विकास निधि के तहत 116.95 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन निधि के तहत 15.12 करोड़ रुपये तथा ग्राम्य विकास निधि के तहत 37.66 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ग्रामीण सहकारी ऋण के लिए बढ़ी संसाधन उपलब्धता

अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण कोष की जमा राशि भी 32,079.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 35,000 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड ने इन जमाओं पर 1,662.89 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया।

नाबार्ड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, कुल अग्रिम बढ़कर 9,30,822.88 करोड़ रुपये हो गए। इनमें ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के तहत 1,98,551.75 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 53,574.88 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण को मिलेगा सहारा

डीसीसीबी पुनर्वित्त, पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण और सहकारी विकास कोष में बढ़ा हुआ वित्तीय सहयोग इस बात का संकेत है कि ग्रामीण सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इससे पीएसीएस से लेकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तक वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नाबार्ड की यह भूमिका किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, सहकारी बैंकों को मजबूत करने तथा गांवों में डिजिटल और आधुनिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रयास सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगा।

मत्स्य समितियों में नवाचार और प्रशिक्षण आवश्यक : नेहरू निषाद

■ **प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों को दी गई योजनाओं की जानकारी**

कुरुद। जिला सहकारी संघ मर्यादित धमतरी द्वारा 25 अगस्त को धीवर समाज सामुदायिक भवन कुरूद में एकदिवसीय जिला स्तरीय प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का विभागीय योजनाओं व मत्स्य पालन के तकनीकी जानकारी तथा शासन की सब्सिडी आधारित योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष नेहरू निषाद, कार्यक्रम के अध्यक्ष मत्स्य महासंघ छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण धीवर, विशिष्ट अतिथि विलासा केवंटिन उपाधि प्राप्त सफल कृषक ग्राम धमधा के रूपचंद धीवर, धीवर समाज कुरुद परगना के संरक्षक भीमसेन तारक , धीवर समाज परगना कुरुद के अध्यक्ष प्रकाश धीवर, सहायक संचालक मछली पालन धमतरी एम एस कमल, प्रवक्ता डॉक्टर ए एन दीक्षित, जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सम्मानीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन उपरांत राम दरबार की पूजा अर्चन कर किया गया।

नई तकनीकों को अपनएं मत्स्य पालक : कमल

कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक संचालक श्री कमल ने कहा कि, सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालकों की दशा सुधारने शासन द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों को नवीनतम तकनीक की जानकारी का प्रयोग कर अपने व्यवसाय को समुन्नत बनाने के साथ शासन की योजनाओं व सहायता की जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित मतस्य सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सहायक संचालक से सवाल किए गए जिसका उन्होंने विधि सम्मत जवाब भी दिए। सी पी साहू ने कहा कि ग्रामीण रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि हेतु सहकारी समितियों का विशेष योगदान के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाने आव्हान किया। प्रकाश धीवर ने शासन द्वारा मछुआरों सहित मत्स्य सहकारी समितियों के हितों एवं उनके संवर्धन व संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें ऐसे प्रशिक्षण सत्रों में आधिकाधिक भागीदारी करके लाभ उठाना चाहिए। रूपचंद धीवर ने कहा कि सहकारिता समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम है।

कमजोर वर्ग के उन्नयन का सशक्त माध्यम है सहकारिता : डा. दीक्षित

प्रवक्ता डॉ दीक्षित ने कहा कि, सहकारिता समाज में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के उन्नयन का एक सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारे भी सहकारी समितियों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान करती है। मत्स्य पालको के कल्याण हेतु जारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हेतु 956 करोड रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 270.37 करोड रुपए जारी भी हो चुके हैं। यह योजना छोटे उत्पादकों के प्रशिक्षण एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर देती है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित मछली आयरलैंड तथा शिकागो तक भेजी जा रही है। मछली बीज की उपलब्धता एवं मत्स्य उत्पादन का विपणन सुधारने हेतु विशेष प्रयत्न किया जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में चौथे नंबर पर तथा मत्स्य उत्पादन में छठे स्थान पर है। प्रदेश में 2.08 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में 9. 59 लाख मीट्रिक टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन हो रहा है। मत्स्य पालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। मत्स्य समिति के सदस्यों को नवाचार, शिक्षण, प्रशिक्षण को आत्मसात कर इस नीली क्रांति को सफल बनाना होगा।

निरंतर काम करने से मिलती है सफलता : रामकृष्ण धीवर

कार्यक्रम अध्यक्ष रामकृष्ण धीवर ने कहा कि, हमें अपने अंदर कभी हीन भावना नहीं आने देना चाहिए। निरंतर कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। सरकार की योजनाएं आपके लाभ के लिए ही बनी है। सरकार की मछुआ नीति मछुआरों के हित में बननी चाहिए। मुख्य अतिथि नेहरू निषाद ने कहा कि आज चिंतन का विषय यह है कि ग्रामीण जनसंख्या को कैसे समृद्ध किया जाए। वर्ष 2025 के सहकारिता वर्ष में इस बात पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 2000 नई समितियां स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों का वित्तीय समावेशन, उत्पादन, प्रबंधन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था में सुधार कर उसे अन्तर्राज्यीय बाजार से जोड़ सके। कृषकों को उन्नत एवं आत्मनिर्भर बनाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि नई मछुआ नीति के प्रारूप पर विचार हो रहा है। इस अवसर पर जिले के मत्स्य सहकारी समितियों के बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मंचस्थ अतिथियों को श्रीफल व साल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता एवं आभार प्रदर्शन भीमसेन तारक ने किया।

नैनो उर्वरकों से नई कृषि क्रांति की ओर बढ़ता बस्तर

- **सहकारी बैंक जगदलपुर में इफ्को की नैनो उर्वरक उपयोग संगोष्ठी में आधुनिक खेती, मिट्टी परीक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर हुई सार्थक चर्चा**

जगदलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर में नैनो उर्वरक उपयोग संगोष्ठी का इफ्को द्वारा आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, नैनो उर्वरकों के प्रभावी उपयोग तथा किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ने के विषय पर सार्थक चर्चा हुई।

नैनो उर्वरकों के प्रभावी उपयोग से बढ़ेगी उत्पादकता : दिनेश कश्यप

संगोष्ठी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने में नैनो उर्वरकों का प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ खेती की लागत को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि, किसानों को नई तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी और उन्नत कृषि पद्धतियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। समृद्ध किसान ही सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से किसानों तक कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और नई तकनीकों की जानकारी पहुंचाना कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पशुपालन- गोबर से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर दें जोर : श्रीनिवास मिश्रा

उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा- हरित क्रांति ने देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी, लेकिन बदलते वैश्विक संकटों के बीच अब हमें खेती में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। नैनो उर्वरकों का संतुलित एवं सही उपयोग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण कार्ड बनाना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें अपनी मिट्टी के गुणों और उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की सही जानकारी हो सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की किसान हितैषी सोच के अनुरूप कृषि के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। पशुपालन से प्राप्त गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी स्वस्थ होगी, तो खेती समृद्ध होगी और किसान खुशहाल होगा। संगोष्ठी को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दी गई समझाइश

संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों में नैनो उर्वरकों के वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आधुनिक कृषि को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ कुंवर सिंह ध्रुव, अतिरिक्त प्रबंधक एस. ए. रज़ा, सहायक संचालक कृषि अजय मीरी, क्षेत्रीय अधिकारी इफ्को एल.बी. सिंह, वैभव पाण्डेय विशिष्ट सहायक इफ्को, एजीटी इफ्को प्रेम प्रकाश साहू सहित बस्तर जिला के समिति प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

निराश्रित बच्चों को प्रशिक्षण से जोड़ने बैंकिंग और सामाजिक संस्थाओं का साझा प्रयास-मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील पहल

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा औद्योगिक घरानों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास और प्रभावी पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन और आत्मनिर्भर जीवन के अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ÷अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाला प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े।÷

उन्होंने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के सामाजिक पुनर्वास के लिए यह पहल प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब इसे विस्तार देते हुए राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

श्रीमती राजवाड़े ने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख श्री विजय तथा कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे से मुलाकात कर बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, कौशल आधारित प्रशिक्षण देने तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। यह पहल बच्चों को केवल संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा देने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा औद्योगिक घरानों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास और प्रभावी पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन और आत्मनिर्भर जीवन के अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है।

इस अवसर पर एक्सिस बैंक के भारत सी.एस.आर. प्रभारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, संस्था से संचालक श्री दीपेश, राज्य प्रमुख श्री जिनेश तथा बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नवगठित लेंपस चोकर में दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

- **ग्राम विकास में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण**
- **नैनो डीएपी, नैनो युरिया विदेशी नहीं बल्कि भारत का उत्पाद**

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर एवं बस्तर जिला सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर व क्षेत्रीय कार्यालय ईफ्को के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत नवगठित लेंपस चोकर लेंपस के आश्रित ग्राम पंचायत भवन में सहकारी एवं कृषक बंधुओं का सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे के द्वारा सहकारिता के अर्थ महत्व सिद्धांत के साथ-साथ नवगठित लेंपस चोकर के सदस्यों को लेंपस के द्वारा प्रदत सेवाएं विशेष कर वित्तीय सेवा विपणन व प्रक्रिया सेवा, उपभोक्ता सेवा, एवं उत्पादन वृद्धि में सहायक विषय पर विस्तार से ज्ञान करवाया जाकर सहकार से समृद्धि हेतु लेंपस संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कृषक बंधुओं को किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत फसल ऋण के साथ-साथ गोपालन बकरी पालन मछली पालन हेतु भी लेंपस से ऋण प्राप्त कर अपनी आय की रास्ते बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया।

नैनो उर्वरकों की दी गई जानकारी

इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी श्री लाल बहादुर सिंह एवं सहायक फील्ड अस्सिटेंट वैभव पांडे द्वारा इफ्को के विषय में विस्तार से बताते हुए नैनो युरिया, नैनो डीएपी एवं कनसुटिया जैसे जैविक उत्पादन के विक्रय एवं प्रयोग विधि की जानकारी दी गई। इससे 2047 के पहले जैविक खेती हेतु किसान अपने आप को तैयार कर अपनी मृदा को भी उसके अनुरूप तैयार कर सकें। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान लेंपस के प्रबंधक श्री गौतम तिवारी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत ऋण सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए लेंपस के सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं चोकर पंचायत के उप सरपंच श्री दिनेश नाग के द्वारा भी यह प्रशिक्षण ग्रामीण किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद प्रशिक्षण बताया गया। प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने में लेंपस के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

सहकारिता : 'मैं' से 'हम' और 'हम' से समृद्धि की यात्रा

किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति केवल उसके संसाधनों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने संसाधनों और सामर्थ्य को कितनी कुशलता से एक साथ जोड़ पाता है। भारत की सामाजिक संरचना में यह सामूहिक शक्ति कोई नई अवधारणा नहीं है। गांव की चौपाल से लेकर श्रमदान तक, सामूहिक खेती से लेकर जल-संरक्षण तक, भारतीय समाज ने सदियों से मिलकर आगे बढ़ने की परंपरा को जिया है। इसी जीवन-दृष्टि का आधुनिक और संगठित आर्थिक स्वरूप है— सहकारिता।

सहकारिता को अगर केवल किसी समिति, संस्था, बैंक या दुग्ध संघ की गतिविधि तक सीमित करके देखा जाए तो हम उसके वास्तविक अर्थ को बहुत छोटा कर देंगे। सहकारिता मूलतः एक विचार है—ऐसा विचार जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता को अकेले खड़ा करने के बजाय उसे सामूहिक शक्ति से जोड़ता है। इसमें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग, केवल लाभ के स्थान पर सामूहिक हित और केवल व्यक्तिगत प्रगति के स्थान पर साझा समृद्धि का भाव दिखाई देता है।

आज देश में आठ लाख से अधिक सहकारी समितियां और लगभग 30 करोड़ सदस्य सहकारी क्षेत्र से जुड़े हैं। कृषि, डेयरी, आवास, श्रम, मत्स्य, उपभोक्ता, विपणन, बैंकिंग, प्रसंस्करण, वस्त्र और अनेक सेवा क्षेत्रों में सहकारिता अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ने भी सहकारी क्षेत्र को आने वाले वर्षों में विस्तृत और व्यापक रूप से विकसित करने के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है।

लेकिन आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह विश्वास, जो एक सहकारी संस्था अपने सदस्य के मन में पैदा करती है।

जब कोई छोटा किसान अपनी उपज के लिए बाजार में अकेला खड़ा होता है, तो उसकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित होती है। लेकिन वही किसान जब हजारों किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी संस्था का हिस्सा बनता है, तो उसकी आवाज मजबूत होती है। जब कोई छोटा उत्पादक अकेले कच्चा माल खरीदता है, तो उसकी लागत अधिक हो सकती है; लेकिन सामूहिक खरीद से वही लागत कम हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अकेले बाजार तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसके सामने कई बाधाएं होती हैं; लेकिन सहकारिता उसे संगठन, बाजार और सामूहिक पहचान देती है।

स्मिता दोडके
प्रदेश महिला अध्यक्ष, सहकार भारती, छत्तीसगढ़

यही सहकारिता की सबसे बड़ी शक्ति है—छोटी-छोटी क्षमताओं को जोडक़र बड़ी आर्थिक शक्ति का निर्माण करना।

अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सहकारिता किन क्षेत्रों में काम कर सकती है। सवाल यह होना चाहिए कि ऐसा कौन-सा क्षेत्र है, जहाँ सहकारिता सामूहिक शक्ति को आर्थिक अवसर में नहीं बदल सकती?

इसी सोच के साथ आज प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स् को केवल ऋण देने वाली संस्था तक सीमित न रखकर उन्हें बहुउद्देशीय आर्थिक गतिविधियों से जोडऩे की दिशा में काम हो रहा है।

सहकारिता का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितनी नई समितियां बनीं। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी सहकारी संस्थाएं कितनी पारदर्शी, सक्षम, आधुनिक और सदस्य-केंद्रित बनती हैं।

इसलिए आज सहकारिता के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता केवल विस्तार की नहीं, बल्कि विश्वास और सुशासन की है।

सहकारिता में व्यक्ति केवल ग्राहक नहीं होता, केवल उत्पादक नहीं होता और केवल निवेशक भी नहीं होता। वह एक साथ सदस्य, सहभागी और स्वामी होता है। इसी लिए सहकारिता का आर्थिक लोकतंत्र से गहरा संबंध है।

भारत की वास्तविक आर्थिक शक्ति उसके गांवों, छोटे शहरों और स्थानीय समुदायों में है। यदि स्थानीय उत्पादन स्थानीय संगठन से जुड़े, स्थानीय संगठन आधुनिक तकनीक से जुड़े और स्थानीय उत्पाद बड़े बाजार से जुड़ें, तो विकास की गति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकती है।

इसे ही हम सही अर्थों में "सहकार से समृद्धि" कह सकते हैं।

इस यात्रा में महिलाओं की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी अब केवल स्वयं सहायता समूहों या कुछ पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। महिलाएं डेयरी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र, वित्तीय सहकारिता और नए उद्यमों में सहकारी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में भी किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास को सहकारिता के परिवर्तन के केंद्र में रखा गया है।

लेकिन महिलाओं की भागीदारी का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना नहीं है। जिस तरह सहकारिता में सदस्य को निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, उसी तरह महिलाओं को भी संस्था की निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए। महिला जब सहकारिता की सदस्य से आगे बढक़र संचालक, उद्यमी और निर्णयकर्ता बनती है, तो सहकारिता की शक्ति कई गुना बढ़ती है।

हमें यह भी समझना होगा कि सहकारिता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार नीतियां बना सकती है, सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है और संस्थागत वातावरण तैयार कर सकती है; लेकिन सहकारिता आंदोलन को जीवंत रखने की जिम्मेदारी स्वयं सहकारियों की है।

सहकारिता में सरकार की भूमिका सहयोग की हो सकती है, लेकिन सहकारिता की आत्मा उसके सदस्यों में होती है।

यहीं से सहकार भारती जैसी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सहकारिता के क्षेत्र में जागरूकता, प्रशिक्षण, अध्ययन, संवाद और सक्षम सहकारी नेतृत्व का निर्माण केवल संस्थाओं को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे सहकारी आंदोलन को वैचारिक आधार देता है। सहकार भारती का उद्देश्य भी सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारियों और सहकारी संस्थाओं की सशक्त श्रृंखला विकसित करना है।

एक ऐसा भारत जहाँ किसान केवल उत्पादक नहीं, अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार हो। जहाँ कारीगर केवल श्रमिक नहीं, अपने उत्पाद का स्वामी हो। जहाँ युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, सामूहिक उद्यम का निर्माता हो। जहाँ महिला केवल परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालने वाली नहीं, सहकारी अर्थव्यवस्था की नेतृत्वकर्ता भी हो।

यही सहकारिता की वह तस्वीर है जिसकी आज आवश्यकता है।

सहकारिता हमें सिखाती है कि समृद्धि अकेले खड़े होकर भी अर्जित की जा सकती है, लेकिन टिकाऊ और व्यापक समृद्धि साथ चलकर ही बनाई जा सकती है।

आखिरकार सहकारिता का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है—

'मैं' की शक्ति सीमित है, "हम" की शक्ति असीमित है।

और जब यही 'हम' ईमानदारी, पारदर्शिता, तकनीक, नेतृत्व और सेवा-भाव के साथ आगे बढ़ता है, तब सहकारिता केवल संस्था नहीं रहती, वह समाज की सामूहिक शक्ति बन जाती है।

आज भारत के सामने सहकारिता को एक नए युग में ले जाने का अवसर है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम सहकारिता को कागज की समितियों से निकालकर लोगों के जीवन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और नए भारत की विकास यात्रा से जोड़ें।

क्योंकि जिस दिन समाज का सामान्य व्यक्ति यह महसूस करने लगेगा कि "इस अर्थव्यवस्था में मेरा भी हिस्सा है, मेरी भी आवाज है और मेरी भी भागीदारी है," उस दिन सहकारिता का उद्देश्य वास्तव में पूरा होगा।

और तब "सहकार से समृद्धि" केवल एक संकल्प नहीं रहेगा—

वह भारत के विकास की जनभागीदारी वाली नई कहानी बन जाएगी।

उद्यमिता की नई मिसाल : बस्तर की महिलाओं ने तैयार की बिना शक्कर वाली ऑर्गेनिक काजू-कतली

■ वन मंत्री केदार कश्यप ने की सराहना

रायपुर। बस्तर अंचल में महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने अपनी लगन और नवाचार के दम पर स्वरोजगार एवं उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल पेश की है। बस्तर वनमंडल (जिला यूनियन जगदलपुर) के अंतर्गत संचालित वन धन विकास केंद्र, बकावंड की धारणी करीन स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय वनोपज का मूल्य-संवर्धन करते हुए बस्तर के ऑर्गेनिक काजू और शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ के अनूठे मेल से बिना शक्कर की स्वास्थ्यवर्धक बस्तर काजू-कतली तैयार की है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने काजू-कतली के स्वाद और महिलाओं की उद्यमशील सोच की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

ऋण से शुरुआत और नवाचार की सफलता

समूह की महिलाओं ने मुख्य वन संरक्षक कार्यालय जगदलपुर के रिवाल्विंग फण्ड से ऋण लेकर बाजार दर पर कच्चे काजू की खरीदी शुरू की थी। प्रसंस्करण के बाद इसे खुले बाजार में बेचकर लाभ कमाने के बाद महिलाओं ने नया प्रयोग करते हुए शक्कर-रहित काजू-कतली बनाई। आधा किलो और एक किलोग्राम की आकर्षक पैकेजिंग में तैयार इस मिठाई को बाजार में ग्राहकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है।

वन मंत्री से मुलाकात और आगामी योजना

स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने सर्किट हाउस जगदलपुर में प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप से सौजन्य भेंट कर उन्हें प्रथम चरण में तैयार की गई बस्तर काजू-कतली भेंट की। महिलाओं ने बताया कि आगामी ऐतिहासिक बस्तर दशहरा और दीपावली के अवसर पर आम नागरिकों के लिए विभागीय आउटलेट शसंजीवनीश् के माध्यम से इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने काजू-कतली के स्वाद और महिलाओं की उद्यमशील सोच की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर सुश्री स्टाइलो मंडावी, मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री उत्तम कुमार गुप्ता और वनमंडलाधिकारी बस्तर श्री दीपेश कपिल को समूह को आवश्यकतानुसार हरसंभव विभागीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

मानव-हाथी द्वंद्व कम करने में हाथी मित्र दल की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री कश्यप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाथी-मानव द्वंद्व को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वन विभाग द्वारा हाथी मित्र दल (हाथी मितान) के सदस्यों को मोटरसाइकिल और सुरक्षा किट (सुरक्षा उपकरण) प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण और जंगल से लगे इलाकों में जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कोरबा प्रवास के दौरान पुतका पहाड़ का निरीक्षण किया और कॉफी प्वाइंट में हाथी मित्र दल के सदस्यों को सुरक्षा उपकरण (किट) वितरित किए।

मंत्री ने किया सुरक्षा किट का वितरण

वन मंत्री श्री कश्यप ने मैदान में तैनात हाथी मित्र दल के सदस्यों को काम के दौरान सुरक्षा संसाधन मुहैया कराने हेतु सुरक्षा उपकरण सौंपे। मंत्री कश्यप ने कहा कि हाथियों की गतिविधियों की सतत निगरानी, ग्रामीणों को समय पर अलर्ट करने और मानव-हाथी टकराव रोकने में दल की भूमिका बेहद अहम है। हाथियों को वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जागरूकता और वन विभाग के मैदानी अमले के साथ समन्वय से द्वंद्व की घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है।

मैदानी अनुभवों पर चर्चा

मंत्री ने सदस्यों से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं और मैदानी चुनौतियों की जानकारी ली तथा उन्हें सुरक्षित रहकर कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर श्री गोपाल मोदी, श्री जोगेश लांबा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल विविधिकरण और आधुनिक तकनीक से खेती बनेगी अधिक लाभकारी : मुख्यमंत्री साय

'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का किया सम्मान

रायपुर। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधिकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विगत दिनों राजधानी रायपुर में आयोजित 'किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम' विषयक संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका जीवन स्वयं खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से खेतों में काम किया और खेती की कठिनाइयों तथा किसानों की आवश्यकताओं को निकट से देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान भी वे नियमित रूप से अपने गांव और खेत की जानकारी लेते थे तथा गांव पहुंचने पर खेत अवश्य जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों या कर्ज पर निर्भर रहते थे, जबकि आज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किए जाने को किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती करना पहले की तुलना में अधिक सहज हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों से किए गए वादों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान की खरीदी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व में लंबित दो वर्ष के बोनस का भी भुगतान किसानों को किया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले खरीफ विपणन सीजन में राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है और राज्य सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, उत्पादन लागत कम करना तथा खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सके।

उन्होंने कहा कि केवल धान आधारित खेती पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को विविध फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

फसल विविधिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए बागवानी, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय के अनेक स्रोत विकसित हो सकें।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं, बैराज, एनीकट तथा नहर विस्तार पर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला हैं सहकारी समितियां : सतीश मराठे

सतीश मराठे ने मजबूत पीएसीएस और नई सहकारी संस्थाओं के गठन पर दिया जोर

सिंधुदुर्ग। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और गांवों में विकास की नई संभावनाएं पैदा करने में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे ने सिंधुदुर्ग के ओरोस में आयोजित 'ग्रामीण सहकारी संवाद' में पीएसीएस को मजबूत करने तथा नई सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम का आयोजन सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं सहकार भारती, सिंधुदुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संवाद में जिले के सहकारी प्रतिनिधियों के साथ किसान, मछुआरे, काजू उत्पादक और युवा उद्यमी शामिल हुए।

ग्रामीण विकास में सहकारिता को मिले केंद्रीय भूमिका

श्री मराठे ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति के अगले चरण में ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसमें सहकारी संस्थाओं को केंद्र में रखना आवश्यक है। पीएसीएस एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना ग्रामीण विकास को व्यापक आधार प्रदान कर सकता है।

उन्होंने सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से अपने-अपने जिलों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने का आह्वान किया, जहां सहकारी संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दे सकती हैं।

डिजिटल परिवर्तन से बढ़ी वित्तीय पहुंच

मराठे ने भारत में हुए डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन का उल्लेख करते हुए कहा कि मोबाइल आधारित भुगतान और डिजिटल वित्तीय सेवाएं अब आम जीवन का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

उन्होंने आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना एवं बीमा योजनाओं जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन से ग्रामीण और कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।

सहकारी शिक्षा और क्षमता निर्माण पर जोर

मराठे ने नव स्थापित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने तथा संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा अल्पकालिक प्रमाणपत्र कार्यक्रमों से लेकर डिग्री स्तर तक विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की जानकारी भी दी गई।

उन्होंने सरकार, सहकारी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय को ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक बताया।

कृषि से पर्यटन तक सहकारिता की संभावनाएं

संवाद के दौरान सिंधुदुर्ग में सहकारी क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने कृषि, मत्स्य पालन, काजू, डेयरी, पर्यटन और ग्रामीण उद्योगों में सहकारी समितियों की भूमिका को विस्तार देने पर चर्चा की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधुदुर्ग डीसीसीबी के अध्यक्ष मनीष दलवी ने की। उपाध्यक्ष अतुल कालसेकर, महाराष्ट्र राज्य काजू निगम के निदेशक एवं सहकार भारती कोंकण प्रभाग प्रमुख धनंजय यादव, डीसीसीबी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरुद्ध देसाई तथा सहकार भारती सिंधुदुर्ग के जिला अध्यक्ष अमित अवाटे सहित अनेक सहकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीएम साय का बड़ा ऐलान : किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में खोले जाएंगे 354 नए धान खरीदी केंद्र

किसानो को उपज बेचने में मिलेंगी बेहतर सुविधा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। प्रदेश के किसानों को धान की उपज बेचने में अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 354 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज के लिए सुगम एवं सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और खरीदी व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत एवं सुविधाजनक होगी।

किसान हित सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी दो वर्षों में लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य भी बताया।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से शासन की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने की दिशा में मिल रही सफलता का भी उल्लेख किया।

किसानों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने वर्ष 2014 से 2026 के बीच देश में हुए विकास कार्यों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किसान हित में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय ने किसान मोर्चा को संगठन का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए जमीनी स्तर पर किसानों से निरंतर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया।

किसान मोर्चा की कार्यसमिति में प्रमुख निर्णय

कार्यसमिति में किसानों से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ किसान हित संबंधी राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री आलोक ठाकुर ने संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

354 नए धान खरीदी केंद्रों की स्थापना राज्य में धान उपार्जन व्यवस्था को किसानों के और करीब ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलने तथा खरीदी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सुकमा में जिला सहकारी संघ के गठन की पहल तेज

- सहकारी संस्थाओं को संगठित कर मजबूत मंच उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा

दोरनापाल। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ के गठन की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा पहल की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सहकारी संघ के संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में सुकता जिले के दोरनापाल में जिला सहकारी संघ के गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने जिले की सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान जिला सहकारी संघ के गठन की आवश्यकता, प्रक्रिया एवं सहकारी संस्थाओं की सहभागिता को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक का उद्देश्य जिले की सहकारी संस्थाओं को एकजुट कर उन्हें एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना तथा स्थानीय स्तर पर सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करना रहा।

श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि जिला सहकारी संघ के गठन से जिले की सहकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को एक मंच पर रखने का अवसर मिलेगा।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में संघ के मानसेवी सदस्य एवं सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम शर्मा, सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मध्य क्षेत्र प्रमुख श्री दिलीप पाटिल सहित श्री प्रदीप शुक्ला, श्री अरजित हलधर, श्री अरूण सुनानी, श्रीमती गीता नाग, श्रीमती बसंती कश्यप, श्रीमती सुशीला कश्यप, श्रीमती ज्योति नायक, श्रीमती पुष्पिता सुनानी, श्रीमती माया खिलारे, श्री पवन, श्री दुर्गेश गुप्ता, श्री सत्यजीत हलधर एवं श्री शुभम सिंह चौहान सहित अन्य उपस्थित रहे।

अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम से बदल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- 24 घंटे राशन की सुविधा, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पारदर्शी वितरण
- कतार और समय की पाबंदी से राहत, हितग्राहियों को मिल रहा निर्धारित मात्रा में पूरा अनाज

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में दुर्ग जिले में 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से 8 अगस्त को गदा चौक के पास अंबेडकर चौक, सुपेला भिलाई स्थित पुराने वैशाली नगर थाना भवन में स्थापित किए गए ग्रेन एटीएम से अब राशनकार्डधारी अपनी सुविधा के अनुसार चावल प्राप्त कर रहे हैं। यह व्यवस्था पारंपरिक राशन दुकानों की कतार और समय की पाबंदी को कम करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को नई दिशा दे रही है।

आधार प्रमाणीकरण के बाद मशीन से मिलता है निर्धारित राशन

ग्रेन एटीएम के माध्यम से दुर्ग जिले के साथ-साथ अन्य स्थानों के राशनकार्डधारी भी चावल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है और पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल मशीन के माध्यम से वितरित किया जाता है। मशीन आधारित वितरण से तौल में कमी की आशंका समाप्त होती है और हितग्राही को उसकी पात्रता के अनुसार पूरी मात्रा में राशन प्राप्त होता है।

24 घंटे उपलब्ध सुविधा से बढ़ी सहूलियत

ग्रेन एटीएम की सुविधा 24×7 उपलब्ध है। इससे दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक, महिलाएं और अन्य राशनकार्डधारी अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार कभी भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में कम समय लगने से हितग्राहियों को कतार में खड़े रहने और निर्धारित समय के भीतर राशन दुकान पहुंचने की बाध्यता से राहत मिल रही है।

तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता, कम हुई निर्भरता

आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण होने से पूरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनी है। हितग्राहियों की उचित मूल्य दुकान संचालकों पर निर्भरता कम होने के साथ राशन वितरण में मानवीय हस्तक्षेप भी घट रहा है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से राशन की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

पीडीएस में तकनीकी नवाचार की नई दिशा

शासन द्वारा अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की सुविधा के संबंध में आम नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र राशनकार्डधारी इस आधुनिक सुविधा का लाभ उठा सकें। ग्रेन एटीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

किसानों को इस साल 904 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण

- नई सहकारी समितियों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश
- सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कामकाज की समीक्षा की

रायपुर। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS) का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर फसल ऋण समय पर मिलते हैं और किसानों को डिजिटल सेवाएं आसानी से मिलने लगती हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभाकक्ष में बैठक लेकर जिला सहकारी बैंक के कामकाज एवं किसानों के हित में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

किसानों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दें : केदार कश्यप

मंत्री श्री केदार कश्यप ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ किसानों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के हित में संचालित केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा। बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती रजनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मिश्रा, नोडल अधिकारी श्री आशीष दुबे सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

ऋण वितरण की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि, वर्ष 2026 में किसानों को 73,207.17 लाख रुपये का नगद ऋण तथा 17,273.35 लाख रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया गया है। इस प्रकार किसानों को 904 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंत्री श्री कश्यप ने ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने तथा सहकारी बैंक की सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

'सहकार से समृद्धि' योजना की भी समीक्षा: मंत्री श्री कश्यप ने 'सहकार से समृद्धि' योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में आईडी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अन्न भंडारण योजना की भी समीक्षा की गई। योजना का शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोदाम निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने अधूरे गोदामों की जानकारी ली। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड एवं संबंधित अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इनका उपयोग किसानों और सहकारी समितियों के हित में किया जा सके। मंत्री श्री कश्यप ने किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार और अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए समय पर ऋण सुविधा मिल सके।

47 नई समितियों में विकसित करें बुनियादी सुविधाएं

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि पांच जिलों में नई 47 सहकारी समितियां खोली गई हैं, जिनमें अकेले बिलासपुर जिले में 16 समितियां शामिल हैं। उन्होंने इन समितियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित क्षेत्रों के किसानों को स्थानीय स्तर पर सहकारिता से जुड़ी सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नई समितियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

सभी सोसायटियों का कंप्यूटराइजेशन पूरा करें

बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। कुछ समितियों में डेटा एंट्री का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस पर मंत्री श्री कश्यप ने 31 अगस्त तक सभी पैक्स में डेटा एंट्री एवं कंप्यूटराइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में ऋण वितरण समितियों की स्थिति, वर्तमान एवं लंबित अल्पकालीन कृषि ऋण, ब्याज अनुदान, माइक्रो एटीएम की उपलब्धता एवं संचालन तथा सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मंत्री श्री कश्यप ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने तथा किसानों को सहकारिता विभाग की सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

शशिकांत द्विवेदी को मिला राज्य मंत्री का दर्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग एवं संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया है। 27 अगस्त 2026 को जारी आदेश में शशिकांत द्विवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को प्रदान किए गए मंत्री दर्जा के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग अथवा आयोग का होगा।

द्विवेदी ने नेताओं का जताया आभार

राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किए जाने पर शशिकांत द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन पवनसाय जी, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी आदि सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनादगांव के रह चुके हैं अध्यक्ष

ज्ञातव्य हो की शशिकांत द्विवेदी पूर्व में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनादगांव के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनंदगांव को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2011 'ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार 'से नवाजा गया था। इसी प्रकार सन 2024 में श्री द्विवेदी को व्यक्तिगत रूप से सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2024 'ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार 'से नवाजा गया है। श्री द्विवेदी पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तत्पश्चात संगठन में भी भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का दायित्व भी पांच वर्षों तक बखूबी निभाया है। उन्हें सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है।

शुभचिंतकों ने दी बधाई

श्री द्विवेदी को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किए जाने से भाजपा समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने द्विवेदी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके अनुभव एवं कुशल नेतृत्व से छत्तीसगढ़ सहकारिता के क्षेत्र में विकास की उम्मीद जताई है।

वनवासियों का हित और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : केदार कश्यप

- तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता पर जोर, कांकेर में भालू के हमलों को रोकने बनेगी विशेष कार्ययोजना

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 322वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्री श्री कश्यप के निवास/कार्यालय में आयोजित हुई।

बैठक में वर्ष 2026 में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेंदूपत्तों के विक्रय के लिए द्वितीय चरण की कार्यवाही तथा वर्ष 2025 सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ता लॉट के विक्रय के लिए प्राप्त निविदाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वन बल प्रमुख श्री अरूण कुमार पाण्डेय, एमडी वनोपज संघ श्रीमती संजीता गुप्ता, प्रभारी अपर प्रधान वन संरक्षक श्री एस. जगदीसन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री ओ.पी. यादव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री माथेश्वरन व्ही. कार्यकारी निदेशक वन श्री एस.वेंकटचलम् सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में तेंदूपत्ता व्यापार, क्रेताओं की नियुक्ति, वनोपजों की बिक्री और वन्यजीवों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री कश्यप ने वनवासियों के आर्थिक हितों के साथ उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

तेंदूपत्ता के 40 लॉट के लिए 15 खरीदार नियुक्त

बैठक में वर्ष 2026 सीजन में संग्रहित और भंडारित तेंदूपत्ता लॉटों के विक्रय की समीक्षा की गई। 4 अगस्त 2026 को हुई द्वितीय चक्र की ऑनलाइन ई-निविदा के आधार पर 40 लॉट के लिए 15 खरीदारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह वर्ष 2025 सीजन के अनुबंध समाप्त तेंदूपत्ता लॉटों के लिए द्वितीय चक्र की ई-निविदा के माध्यम से 6 लॉट के लिए 3 खरीदारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा मिलेगा।

वनवासियों का हित और सुरक्षा सर्वोपरि

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तेंदूपत्ता व्यापार में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णयों से संग्राहकों को लाभ मिलेगा। वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पिछली बैठक के निर्णयों की हुई समीक्षा

बैठक में समिति की 321वीं बैठक में लघु वनोपज संघ से संबंधित लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ प्रगति की सराहना की गई।

कांकेर में भालू के हमलों को रोकने बनेगी विशेष कार्ययोजना

बैठक में कांकेर जिले और आसपास के वन क्षेत्रों में भालुओं की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों की सुरक्षा का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। मानव-वन्यजीव संघर्ष और जनहानि को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। भालुओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में वन विभाग को लगातार निगरानी रखने और ग्रामीणों को समय पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ग्रामीणों और वनवासियों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया, ताकि लोग वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

तेंदूपत्ता से आर्थिक मजबूती, सुरक्षा से बढ़ेगा भरोसा

राज्य सरकार की प्राथमिकता वनवासियों को उनकी मेहनत का उचित लाभ दिलाने के साथ ही वन क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। तेंदूपत्ता सहित लघु वनोपज के व्यापार में पारदर्शी व्यवस्था से संग्राहकों के आर्थिक हित मजबूत होंगे, वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयास ग्रामीणों के जीवन में सुरक्षा और भरोसा बढ़ाएंगे।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफ्सेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcàæàæp.in E-mail- cgcàæàæpnews@gmail.com